डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 अप्रैल, 2021, डिस्पेच दिनांक 1 अप्रैल, 2021

| वर्ष 64 | अंक 21 | भोपाल | 1 अप्रैल, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

ग्रामोदय मिशन से आएगी खुशहाली और गाँवों का होगा समग्र विकास : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने किया मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नगरोदय मिशन के बाद आज से पूरे प्रदेश में मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएँ देने के साथ ही मूलभूत और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इससे ग्रामीणों के चेहरों पर नई मुस्कुराहट और उनके जीवन में नई खुशहाली आयेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज धार में ग्रामोदय मिशन के राज्य–स्तरीय कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर असम से वर्चुअली शामिल हुए।

कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में बनाये 3 लाख आवास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बेघरों के लिए तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी 3 लाख आवास का निर्माण पूरा कर जरूरतमंद परिवारों को दिए गए। हमारा प्रयास है कि वर्ष 2022 तक कोई भी आवासहीन नहीं रहे, सबका पक्का मकान हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है। किसानों की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। किसानों के हक की बीमा राशि, राहत राशि, सम्मान निधि सहित अन्य सभी सुविधाएँ दी जाएँगी। उन्होंने कहा कि बैंकों में बकाया कृषि ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए मिशन ग्रामोदय प्रारम्भ किया गया है। इसमें हर गाँव में पक्की सड़क का निर्माण, हर ग्राम पंचायत का भवन, हर ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम और खेल मैदान होंगे। हर गाँव के हर घर में नल से जल पहुँचाया जाएगा। इस वर्ष 26 लाख घरों में नल से जल पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। अगले 3 वर्षों में एक करोड़ 2 लाख घरों में नल से जल पहुँचाने का कार्य किया जायेगा। मिशन ग्रामोदय में स्व–सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उन्हें मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। स्व–सहायता समूहों को स्कूलों के बच्चों की ड्रेस बनाने तथा आँगनवाड़ियों के लिए पोषण आहार बनाने का कार्य सौंपा जा रहा है।

संबल योजना का लाभ हर जरूरतमंद परिवार को

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना पुनः शुरू की गई है। इसके हर घटक का लाभ हर जरूरतमंद परिवार को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्नत स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए 1500 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। ऐसे स्कूल के बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में भगोरिया सहित अन्य किसी भी त्यौहार एवं पर्व को मनाने पर रोक नहीं है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

फसल ऋण वसूली अवधि एक माह बढ़ेगी : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान हितेषी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होने वाली फसल ऋण वसूली की अवधि को 1 माह बढ़ाए जाने पर सहमति प्रदान कर दी है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट कर फसल ऋण वसूली की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपार्जन का कार्य चल रहा है और किसानों को उपज की राशि अप्रैल–मई माह में प्राप्त होगी। एक माह की अवधि बढ़ने से अब किसानों की मुश्किल कम होगी और वे फसल ऋण की राशि को जमा कर सकेंगे।

संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि 6 माह बढ़ाई

सहकारिता मंत्री के निर्देश पर

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया के निर्देश पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में सीबीएस कार्य के लिये संविदा, आउटसोर्स पर रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एल–1 इंजीनियर की सेवा अवधि में वृद्धि कर दी गई है। संयुक्त आयुक्त ने निर्देश जारी किए हैं कि सीबीएस कार्य के लिये रखे गए जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी थी उनकी सेवा अवधि को 20 जिलों के सहकारी केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त परीक्षणोपरांत आगामी 6 माह के लिये बढ़ा दिया गया है।

महासंघ ने जताया आभार

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया का संविदा लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने पुष्प गुच्छ भेंट कर सेवा अवधि बढ़ाने के लिए आभार जताया। मंत्री डॉ. भदौरिया से महासंघ के उपाध्यक्ष श्री अंकुर दुबे सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि मंत्री डॉ. भदौरिया के निर्देश पर संविदा लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर्स महासंघ की मांग पर परीक्षणोपरांत सहकारी केंद्रीय बैंकों में सी. बी.एस. कार्य के लिए जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी थी उनकी सेवा अवधि में 6 माह की वृद्धि की गई है।

मध्यप्रदेश बना गेहूँ प्रदेश

• मुकेश दुबे

मुख्यमंत्री बनाम चुनौतियों पर विजय का साल

चुनौतियाँ सफल मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण भाग है परंतु महत्वपूर्ण यह है कि उन चुनौतियों का सामना आप किस प्रकार करते हैं। शायद कुछ ऐसा ही समय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सामने आया जब 23 मार्च 2020 को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खाली खजाने के साथ कोरोना की चुनौती और प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की जीवन रक्षा का प्रश्न सामने खड़ा था।

न मंत्री और न मंत्री–मंडल, खुद ही मंत्री खुद ही मुख्यमंत्री। वक्त मुश्किल था पर हौंसला बुलंद था। एक सदस्यीय मंत्री–मंडल ने शपथ के दिन ही मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा से अपने नेतृत्व कौशल का परिचय दिया। चारों ओर चुनौतियाँ, बस जीत का था विश्वास, तो पीछे था प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हाथ।

कोरोना से लड़ाई लड़नी भी थी तो घर में बैठकर क्योंकि कोरोना से बचाव ही कोरोना पर जीत का मुख्य अस्त्र थी। प्रधानमंत्री के आव्हान पर देश–प्रदेश की जनता अपना कामकाज चंद घंटों में ही जहाँ जिस हाल में था, बंद कर अपने घरों में कैद हो गई। कहते हैं खाली पेट कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती। मुख्यमंत्री श्री चौहान के सामने बड़ी चुनौती थी घर में बैठकर कोरोना संक्रमण से लड़ रही अपनी जनता रूपी सेना को राशन कैसे पहुँचाए। उधर गेहूँ खेतों में तैयार खड़ा था। पहले गेहूँ की उचित मूल्य पर खरीदी फिर भंडारण एवं उसका वितरण वो भी जनता को घर–घर जाकर।

1.29 करोड़ मी.ट.गेहूँ का उपार्जन

कोरोना लॉकडाउन के सन्नाटे के बावजूद मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर एक करोड़ 29 लाख 28 हजार 379 मीट्रिक टन गेहूँ का बम्पर उपार्जन किया गया। यह देश के किसी भी राज्य द्वारा किये गए उपार्जन में सबसे अधिक है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 25 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया, जो विगत वर्ष 2018–19 में किए गए भुगतान से लगभग 11 हजार करोड़ रूपये अधिक था। इस वर्ष भी 2021–22 के लिए किसानों ने अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन करा लिया है। उपार्जन का काम इंदौर और उज्जैन में 22 मार्च से और शेष स्थानों पर एक अप्रैल से प्रारंभ होगा।

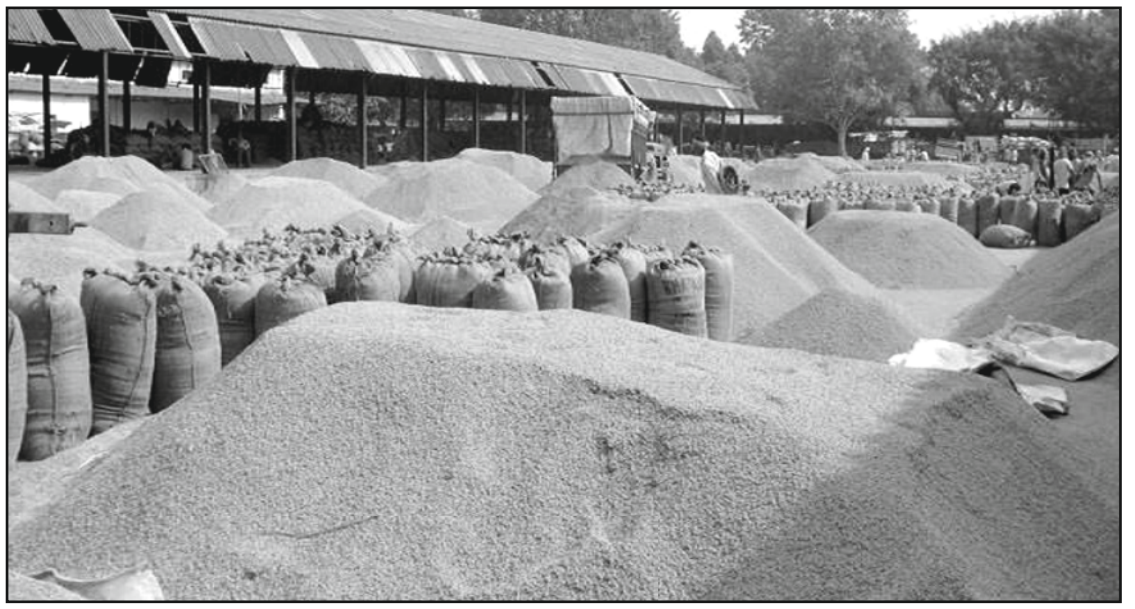

तुरंत ऑन लाइन भुगतान

प्रदेश के 4हजार 527 खरीदी केन्द्रों पर 15 लाख 55 हजार 453 किसानों से उनकी समर्थन मूल्य पर क्रय की गई उपज के भुगतान स्वरूप राशि ऑन लाइन उनके खातों में अंतरित की गई। इस वर्ष 2021–21 के लिए प्रदेश में 19 लाख 46 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन कराया था। इसमें से 15 लाख 29 हजार किसानों ने 122 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का विक्रय किया। किसानों को सफल भुगतान के रूप में 16 हजार 183 करोड़ 77 लाख 21 हजार 757 रूपये की राशि ऑनलाइन भुगतान उनके खातों में पहुँचायी जा चुकी है।

निश्चित अवधि में लक्षित उपार्जन

कुल उपार्जित गेहूँ का 87.33 प्रतिशत यानी एक करोड़ 7 लाख 27 हजार 926 मीट्रिक टन गेहूँ का परिवहन किया जाकर उसे सुरक्षित गोदामों में भंडारित कराया गया। लॉक डाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विपरीत परिस्थितियों में गेहूँ का निश्चित अवधि में उपार्जन मानसून को देखते हुए जरूरत के साथ एक उपलब्धि भी है।

छोटे एवं मध्यम किसान हुए लाभान्वित

इस एक वर्ष में प्रदेश के कुल पंजीकृत किसानों में से 13 लाख 80 हजार लघु, मध्यम एवं सीमांत किसानों ने अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय किया। इनमें लगभग 3 लाख 81 हजार सीमांत किसान शामिल हैं जबकि 5 लाख 41 हजार छोटे किसानों सहित 4 लाख 68 हजार मध्यम किसानों ने उपार्जन का लाभ लिया। लघु, मध्यम एवं सीमांत किसानों ने 86.57 मीट्रिक टन गेहूँ का विक्रय किया। इनमें से सीमांत किसानों ने अभी तक कुल 9 लाख 26 हजार मीट्रिक टन, छोटे किसानों ने 28 लाख 38 हजार मीट्रिक टन और मध्यम किसानों ने 48 लाख 93 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया है। शेष गेहूँ बड़े किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया।

प्रदेश को गेहूँ प्रदेश बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो है प्रदेश का किसान, प्रदेश का अन्न–दाता। सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अच्छे उत्पादन के चलते इस साल 16 लाख किसानों से बम्पर गेहूँ उपार्जन करके एक नया इतिहास बनाया गया है। इस तरह मध्यप्रदेश गेहूँ उपार्जन में देश का नंबर वन राज्य बना।

इस सफलता को पुनः दोहराते हुए प्रदेश में धान के उपार्जन का कार्य भी सफलता पूर्वक संपादित किया गया। इसीका परिणाम है कि जनवरी 21 तक 5 लाख 86 हजार से अधिक किसानों से 37 लाख 27 हजार मीट्रिक टन से अधिक मात्रा में धान उपार्जित किया गया। इसके अलावा 42 हजार 400 से अधिक किसानों से 2 लाख 24 हजार मीट्रिक टन से अधिक ज्वार एवं बाजरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। गेहूँ,धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन के विरूद्ध 33 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई।

राशन का सुनियोजित वितरण

उपार्जन के बाद सरकार के सामने अपनी जनता को राशन वितरण की चुनौती थी। चुनौती इसलिए कि कोरोनो के कारण लगे लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वितरण के साथ करना था। सरकार ने एक करोड़ 10लाख पात्र परिवार के 4 करोड़ 72 लाख सदस्यों को खाद्यान्न सुरक्षा के तहत राशन वितरण कर इसे बखूबी पूरा किया। अन्त्योदय अन्न योजना में पात्र परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार और प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से किया गया।

''वन नेशन – वन राशन कार्ड'' योजना

प्रदेश के बाहर रहने वाले प्रदेश के नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ''वन नेशन–वन राशन कार्ड'' योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हितग्राही अब प्रदेश के बाहर जिस राज्य में वे रह रहे हैं वहाँ से खाद्यान्न लेने के लिए स्वतंत्र है। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के माध्यम से माह जनवरी तक 3 लाख 85 हजार से अधिक परिवारों को खाद्यान्न प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अपने क्षेत्र में किसी भी दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है।

अन्न उत्सव

राज्य शासन द्वारा यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि गरीब की थाली किसी भी हालत में खाली न रहे। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के नवीन चिन्हित व्यक्तियों को पात्रता पर्ची जारी की गई, जो अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन प्राप्त करने से वंचित थे। ''अन्न उत्सव'' कार्यक्रम के माध्यम से 25 श्रेणियों के नवीन पात्रता पर्चीधारी 6 लाख 46 हजार से अधिक परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। अब तक ऐसे लगभग 9 लाख परिवारों के लगभग 31 लाख सदस्यों को नियमित राशन वितरण किया गया है।

चना, मसूर, सरसों का उपार्जन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 3 लाख किसानों से 8 लाख से अधिक मीट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन कर 3 हजार 900 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किसानों को किया गया।इसी के साथ खरीफ में 5 लाख 89 हजार किसानों से 37 लाख 26 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। किसानों को उपार्जित धान की कुल राशि 6 हजार 961 करोड़ रूपये भुगतान की गई। इसी प्रकार एक लाख 95 हजार मीट्रिक टन बाजरा एवं 29 हजार मीट्रिक टन ज्वार का उपार्जन किया गया है।

किसानों के गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जाएगा : मुख्यमंत्री

अब तक 24 लाख 58 हजार किसानों ने कराया गेहूँ पंजीयन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के गेहूँ का एक–एक दाना खरीदा जाएगा। सभी जिलों में गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएँ अग्रिम रूप से सुनिश्चित की गई है। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिये व्यापक प्रबंध किये जाकर उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। समय पर किसानों की फसल का उपार्जन हो और उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरे लिए एक–एक किसान महत्वपूर्ण है। किसी भी किसान का भुगतान रुकना नहीं चाहिए। उपार्जित फसल के तुरंत परिवहन की भी व्यवस्था की जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएँ प्राथमिकता के आधार पर की जा रही उन्होंने बताया कि गेहूँ उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन से कोई किसान चूके, नहीं इसके लिये पंजीयन की तिथि में दो बार वृद्धि भी की गई हैं।

4763 उपार्जन केन्द्रों पर होगी खरीदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में किसानों की सुविधा के लिये उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस बार 4763 केंद्र पर उपार्जन की व्यवस्था की गई है। सभी उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिये माकूल व्यवस्थाएँ भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से अपील की है कि वे निश्चिंत होकर अपना गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर लाए। सभी किसानों के गेहूँ का एक–एक दाना सरकार खरीदेगी। इस बार समर्थन मूल्य पर 125 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। अभी तक 24 लाख 58 हज़ार किसानों ने गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगा। गत वर्ष यह 1925 रुपए प्रति क्विंटल था।

चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन इस बार उपार्जन का कार्य मार्कफेड करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि चने का समर्थन मूल्य 5100 रूपये, सरसों का समर्थन मूल्य 4650 रूपये और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रूपये प्रति क्विंटल है। चने का उपार्जन 14 लाख 51 हजार टन, मसूर का एक लाख 37 हजार टन और सरसों का 3 लाख 90 हजार टन अनुमानित है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि कोई भी किसान अपनी उपज को बेचने से वंचित न रहे और सभी किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर हो। किसान को भुगतान न होना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे दोषी व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क की जाकर उन्हें जेल भेजें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, उन्हें इस बार उपार्जन का कार्य न दिया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत वर्ष की तरह इस बार भी स्व–सहायता समूहों तथा कृषि उत्पादक समूहों को उपार्जन कार्य दिया जाएगा। गत वर्ष 39 उपार्जन केंद्रों पर स्व–सहायता समूहों एवं कृषि उत्पादक समूहों द्वारा 9 लाख 78 हज़ार 526 क्विंटल गेहूँ उपार्जित किया गया, जो कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत था।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का जो इतिहास रचा गया, उसके मूल में किसानों की कड़ी मेहनत है। प्रदेश के किसानों ने मध्यप्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के इतिहास में समर्थन मूल्य पर हुई रिकार्ड खरीदी में सरकार द्वारा की गई चाक–चौबंद व्यवस्थाओं ने भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।

किसान उन्नत तकनीकी का उपयोग कर कम लागत में अधिक लाभ लें : डॉ. मिश्रा

दतिया में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत गन्ना उत्पादक कृषकों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

भोपाल। परम्परागत खेती के साथ बदले वातावरण में कृषि में आधुनिक एवं उन्नत तकनीकी का उपयोग कर किसान कम लागत में अधिक लाभ लें। डॉ. मिश्रा "एक जिला एक उत्पाद" योजना के तहत शुक्रवार को दतिया के वृंदावन धाम में आयोजित गन्ना उत्पादक कृषकों की कार्यशाला एवं वैज्ञानिक परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि दतिया के किसान मेहनत, लगन, वैज्ञानिकों की सलाह एवं शासन की योजनाओं का लाभ लेकर उन्नत तकनीकी का उपयोग कर कम लागत में अधिक उत्पादन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर क्षेत्र में क्रांति आई है। कृषि का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। किसानों को बदली हुई परिस्थिति अनुसार खेती– किसानी के तौर तरीकों में बदलाव लाना जरूरी हैं। कृषि के क्षेत्र में उन्नत एवं आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर अधिक उत्पादन लेने का प्रयास कर आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाना है।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि डबरा की सुगर फैक्ट्री में शक्कर निर्माण में जिले के गन्ना उत्पादक किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसानों के द्वारा पैदा किए गए गन्ने के कारण ही डबरा को शक्कर के रूप में पहचान मिली है।

गुणवत्तापूर्ण गुड़ को बेहतर मार्केटिंग से विशेष पहचान दिलायें

डॉ. मिश्रा ने कहा कि दतिया जिले के गोराघाट क्षेत्र में उत्पादित गन्ने से मेरठ से भी अच्छा गुड़ बनाया जा रहा है। गोराघाट के गुड़ को पहचान दिलाने के लिये किसान उन्नत किस्म का गन्ना पैदा कर उन्नत तकनीकी का उपयोग कर बेहतर गुणवत्ता का गुड निर्माण करें। डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र लखनऊ के वैज्ञानिकों द्वारा गन्ना उत्पादन के संबंध में जो तकनीकी मार्गदर्शन एवं गन्ने की उन्नत किस्में बोने की सलाह अनुसार गन्ने की फसल लें। डॉ. मिश्रा ने कहा कि गन्ने से बनने वाले सीरे का उपयोग ईधन निर्माण में भी किया जा रहा है। गन्ने की खोई का भी उपयोग बिजली उत्पादन में लिया जा रहा है।

किसान कुटीर उद्योग स्थापित करें

डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसान भाई आलू, टमाटर पर केन्द्रित चिप्स एवं सॉस के गांव में कुटीर उद्योग स्थापित कर आय के साधन बढ़ा सकते हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि गौ–माता का गोबर भी काफी उपयोगी है। गाय के गोबर से पेंट का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल में मुक्तिधामों में अंतिम संस्कार में गोवर से बनी लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है।

वैज्ञानिकों का किया सम्मान

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कार्यशाला में भारतीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र लखनऊ के कृषि वैज्ञानिक डॉ. एस.एन सिंह, डॉ. एम.आर. सिंह, डॉ. एस.आई हेमर और कृषि विज्ञान केन्द्र दतिया के डॉ. पुनीत कुमार राठौर का भी शॉल, श्रीफल एवं पुष्पहार से सम्मान किया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्री रविन्द्र पाराशर ने कार्यशाला के उद्देश्यों एवं महत्व पर प्रकाश डाला। श्री सुरेन्द्र बुधौलिया, पूर्व विधायक डॉ आशाराम अहिरवार सहित श्री पंकज शुक्ला,जीतू कमरिया एवं अन्य जनप्रतिधिनिगण व किसान उपस्थित थे।

वानिकी विकास योजनाओं से सँवर रहा है मध्यप्रदेश का ग्रामीण परिवेश

मध्यप्रदेश में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए की जा रही प्रभावी पहल के चलते वनों के साथ–साथ उन पर आश्रित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वानिकी विकास के जरिए समृद्ध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पिछले एक साल में वनों की सुरक्षा और विकास के साथ–साथ वनों पर आश्रित वनवासियों के कल्याण की नई इबारत लिखी गई है।

प्रदेश में वन–जन को समन्वित कर वानिकी में भागीदारी का अंश बढ़ाने के साथ ही 'जन' की सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन की विचारधारा को सशक्त रूप से अपनाया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए 9784 ग्राम वन, 4773 वन सुरक्षा और 1051 ईको विकास समितियाँ गठित हैं। इनके माध्यम से करीब 47 हजार वर्ग किलो मीटर वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है।

संयुक्त वन प्रबंधन से समृद्ध समितियाँ 33 फीसदी पद महिलाओं को

वन समितियों में 33 फीसदी महिलाओं की सदस्यता आरक्षित की गई है। साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में से एक पर महिला की नियुक्ति अनिवार्य की जाकर महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाया गया है। वन खंड की सीमा से 5 कि.मी. दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, चराई और अग्नि से क्षेत्र की सुरक्षा का काम करती हैं। इसके ऐवज में उन्हें आवंटित क्षेत्र से समस्त लघु वनोपज, रॉयल्टी मुक्त निस्तार एवं काष्ठ विदोहन का 20 प्रतिशत लाभांश दिया जाता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अमयारण्य के बफर क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों में ईको विकास समिति गठित है। यह समितियाँ सामाजिक–आर्थिक उत्थान के कार्य में संलग्न हैं।

34 करोड़ का दिया गया लाभांश

जिलास्तर पर काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ 20 फीसदी वन प्रबंधन समितियों को 22 करोड़ 56 लाख रूपये की राशि दी गई। बाँस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बाँस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि शत–प्रतिशत दी जाती है। इसमें 11 करोड़ 39 लाख रूपये का लाभांश दिया जा चुका है। इस तरह कुल 33 करोड़ 95 लाख रूपये का लाभांश वितरित किया जा चुका है।

बाँस रोपण से बढ़ी किसानों की आमदनी

प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि फसलों के साथ बाँस रोपण एक बेहतर विकल्प के रूप में लोकप्रिय हुआ है। इस वित्त वर्ष में 3597 किसानों ने 3228 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया। जिस पर उन्हें पौने 7 करोड़ रूपये से ज्यादा का अनुदान दिया गया। स्व– सहायता समूहों को 'आत्म–निर्भर' बनाने के लिए मनरेगा में 83 स्व–सहायता समूह के माध्यम से 1020 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया गया। अन्य योजनाओं में भी 1248 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस रोपण किया गया। निजी क्षेत्र में मंजूर की गई 13 बाँस प्र–संस्करण इकाइयों में से 9 इकाई प्रारंभ हो चुकी है। इन इकाइयों को 1 करोड़ 68 लाख रूपये का अनुदान वितरित किया गया।

संग्राहको को 397 करोड़ रूपये की मिली मजदूरी तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों का सँवारा जा रहा भविष्य

लघु वनोपज संघ द्वारा 'एकलव्य शिक्षा विकास योजना' के जरिए तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़–मुंशी और प्रबंधकों के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों में सहायता प्रदान कर उनका भविष्य सँवारा जा रहा है।

इस वित्त वर्ष में शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए अब तक करीब एक हजार छात्र–छात्राओं को 9 करोड़ 88 लाख से ज्यादा की सहायता दी गई।

प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण में 33 लाख संग्राहक जुड़े हैं। इनमें 44 फीसदी महिलाएँ हैं। अधिकत्तर संग्राहक अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हैं। इन्हें लगभग एक माह का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इन संग्राहकों को आर्थिक संबल देने के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक तथा प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस के रूप में दिया जाता है। पिछले वर्ष 15 लाख 88 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित कर संग्राहकों को 397 करोड़ रूपये का पारिश्रकि दिया गया। वर्ष 2018 में संग्रहीत और तेन्दूपत्ते के व्यापार से हुए शुद्ध लाभ में से 183 करोड़ 31 लाख की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दी गई । मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक सहायता योजना में इस वित्त वर्ष में अब तक 2 करोड़ 26 लाख 20 हजार रूपये की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है।

32 लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित 86 वन–धन विकास केन्द्र

लघु वनोपज के संग्राहकों द्वारा संग्रहित वनोपज का प्राथमिक उपचार कर सही मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए वन–धन विकास योजना के तहत ट्राइफेड द्वारा पहले चरण में 13 जिलों में 86 वन–धन विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 10 स्व–सहायता समूह क्लस्टर का एक केन्द्र है। इसमें प्रत्येक स्व–सहायता समूह के 30 सदस्य रखे गए हैं। इससे 50 करोड़ रूपये का व्यापार संभावित है। प्रदेश में 32 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के समकक्ष और कुछ वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार की दरों से भी ज्यादा है।

वन–धन विकास केन्द्र योजना

लघु वनोपज संग्राहकों द्वारा संग्रहीत वनोपज का प्राथमिक प्र–संस्करण एवं मूल्य संवर्धन द्वारा उचित मूल्य दिलाने के लिए यह अभिनव योजना शुरू की गई है। एक वन–धन केन्द्र में 300 संग्राहक हैं। राज्य लघु वनोपज संघ, क्रियान्वयन ऐजेन्सी है।

वन रोपणियों के पौधों से मिला 5 करोड़ का राजस्व

प्रदेश में वानिकी वृत्तों की 170 रोपणियाँ हैं। इन रोपणियों से 3 करोड़ 42 लाख पौधों की बिक्री और 50 लाख सागौन रूट–शूट की नीलामी से 4 करोड़ 99 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष रोपण के लिए पौधा तैयारी का कार्य भी प्रगति पर है। रोपणियों के पौधों को ऑन–लाईन संधारण के लिए नर्सरी मैनेजमेन्ट विकसित किया गया है। कुछ रोपणियों में सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाए जाकर उनकी सुरक्षा और निगरानी की जा रही है।

निजी क्षेत्रों में वानिकी प्रोत्साहन

वनोपज की मांग और आपूर्ति के बढ़ते अन्तर को कम करने और किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए निजी भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2020 में गैर वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजाति के करीब सवा 6 लाख पौधों का रोपण कराया गया। आम लोगों को एम.पी. ऑन–लाईन के माध्यम से भी पौधे उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

वन विकास

वनों की संवहनीयता बनाए रखने के लिए बिगड़े वनों का सुधार, वृक्षारोपण आदि कार्य किए जाते हैं। वर्ष 2020 में करीब पौने 6 करोड़ पौधे लगाए गए। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्य सरकारों से संपर्क कर प्रदेश के बिगड़े वनों के सुधार में निवेश लाने का प्रयास किया जा रहा है। अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने मध्यप्रदेश सरकार से बिगड़े वनों के सुधार के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण करने का अनुरोध किया है। इसके लिए तैयार की गई परियोजना से तकरीबन 40 हजार से अधिक हेक्टेयर बिगड़े वनों के सुधार में 1500 करोड़ रूपये उपलब्ध होंगें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

वन संरक्षण

प्रदेश में वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। बीट प्रभारी के अलावा परिक्षेत्र सहायक से लेकर वन मण्डलाधिकारी स्तर तक के अधिकारी रोस्टर अनुसार वनों के अवैध रूप से काटे वृक्षों की जाँच कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हैं। अपराधियों से निपटने के लिए 3157 बन्दूक और 286 रिवाल्वर उपलब्ध कराए गए हैं। चौदह अति संवेदनशील वन मण्डलों में विशेष सशक्त बल की 3 कंपनी के जवान,वन, वन्य–प्राणी एवं वन कर्मियों की सुरक्षा करते हैं। सभी 16 वन क्षेत्रों में उड़न दस्ता दल गठित है, जो समय–समय पर स्थानीय अमले को अतिरिक्त सुरक्षा–सहायता प्रदान करता है।

वन उत्पादन

राज्य में मुख्य रूप से साल, बाँस तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वृक्ष मौजूद हैं। वानिकी वर्ष 2020–21 में अब तक एक लाख घन मीटर इमारती काष्ठ, 5 हजार जलाऊ चट्टे और 15 हजार नोशनल टन विक्रय इकाई बाँस का उत्पादन हुआ है।

निस्तार व्यवस्था

वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवार को ही घरेलू उपयोग के लिए बाँस, छोटी ईमारती लकड़ी (बल्ली) हल, बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। स्वयं के उपयोग के लिए वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी पड़ी, मरी और सूखी जलाऊ लकड़ी की सुविधा भी दी जा रही है। वर्ष 2020 में निस्तार के लिए 19 लाख 61 हजार नग बाँस, 16 हजार बल्ली और 51 हजार जलाऊ चट्टे ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जाने के साथ ही 9 करोड़ 12 लाख रूपये की रियायत भी दी गई।

राजस्व आय में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से इस वित्त वर्ष में जनवरी 2021 तक की स्थिति में 1010 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। कोरोना जैसी महामारी और लॉक डाऊन के रहते राजस्व अर्जित करने के मामले में यह उपलब्धि विशेष मायने रखती है।

वन भूमि व्यपवर्तन

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वर्ष 2020 में 46 प्रकरणों में भारत सरकार से 2685.547 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसी अवधि में 15 प्रकरण में 1117.239 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की सैद्धान्तिक सहमति भी प्राप्त हो चुकी है।

वानिकी से अगले साल मिलेगा लाखों लोगों को रोजगार

अगले वित्तीय वर्ष में विभिन्न वानिकी कार्य वृक्षारोपण, पुनर्त्पादन, उत्पादन, वन सुरक्षा, लघु वनोपज का संग्रहण, भण्डारण एवं ईको पर्यटन, होम स्टे आदि से करीब पौने 8 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प है।

आत्म निर्भर मध्यप्रदेश में महिलाओं की होगी सशक्त भागीदारी : मुख्यमंत्री

महिला स्व–सहायता समूहों को भी निरन्तर मिलेगा आर्थिक संबल

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता में लिया गया है, जिससे प्रदेश की महिलाएँ अपने हुनर से आत्म–निर्भर बनेगीं और मध्यप्रदेश को आत्म–निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये राज्य सरकार उन्हें हर संभव मदद कर रही है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, महिला–कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक उन्नति, रोजगार, समानता, बेटी–बचाओं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कार्य किये जा रहे है। महिलाओं और बच्चियों के लिये अनेक योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं, इन योजनाओं का लाभ उन्हें उनके हक के आधार पर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है, जो महिलाएँ नहीं कर सकती। मध्यप्रदेश में महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के गम्भीर प्रयास किये जाएंगे, जिससे महिलाओं की सशक्त भागीदरी प्रदेश के विकास में सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्व–सहायता समूहों को आर्थिक संबल देने का कार्य निरंतर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के महिला स्व–सहायता समूहों के खातों में 200 करोड़ रूपये अंतरित किये गये हैं। अब प्रत्येक माह समूहों के खाते में 150 करोड़ रूपये डाले जाएंगे। महिला स्व–सहायता समूहों को अब 4 प्रतिशत दर की जगह 2 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। शेष ब्याज की राशि सरकार देगी। महिला स्व–सहायता समूहों को इस बार गेहूँ और अन्य फसलों की खरीदी से भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही मध्यान्ह भोजन में प्रयुक्त सामग्री भी महिला स्व–सहायता समूह से क्रय की जाएगी। पंचायत स्तर पर होने वाले सर्वेक्षणों, मनरेगा के तहत 50 प्रतिशत मेट महिला स्व–सहायता समूह की सदस्य होगी। शासकीय स्कूलों के बच्चों की यूनिफार्म बनाने का काम भी महिला स्व–सहायता समूहों को सौंपा गया है। कुल मिलाकर प्रदेश में महिला स्व–सहायता समूहों के

माध्यम से लोकल को वोकल बनाया जा रहा है।

घर–परिवार में महिलाओं का वजूद बनाने के लिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जमीन में पति के साथ पत्नी का नाम जोड़ना जरूरी होगा। नई सम्पत्ति बहन, माँ, बेटी, पत्नी के नाम पर खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में दो प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी किया। आवास योजनाओं में पति–पत्नी दोनों का संयुक्त नाम होगा।

पुरूष प्रधान मानसिकता को बदलने के लिये उमंग कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसमें कक्षा 9वीं से 11वीं के बच्चों को लड़कियों को इज्जत देने के संस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में बच्चियों के प्रति अपनत्व जगाने के लिये शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना में आज 38 लाख से अधिक प्रदेश की बेटियाँ लाड़ली लक्ष्मी हैं। इन लाड़ली लक्ष्मियों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है। आई.आई.टी., आई.आई.एम, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सहित देश–विदेश में इनकी उच्च शिक्षा की फीस सरकार वहन करेगी। प्रदेश में शीघ्र ही नारी सम्मान कोष भी स्थापित किया जाएगा।

प्रदेश में महिलाओं के लिये संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ केन्द्र सरकार की महिलाओं संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश हमेशा अग्रीण भूमिका निभाता रहा है। हाल ही में केन्द्रीय महिला–बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा की गई। इसमें योजना के सफल क्रियान्वयन और 152 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने पर मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर प्रथम स्थान दिये जाने की घोषणा की गई है। योजना अन्तर्गत समस्त गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को प्रथम जीवित जन्मे बच्चे पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति उपरान्त प्रति हितग्राही 5 हजार रूपये तीन किस्तों में दिये जाने का प्रावधान है।

बेटियों और महिलाओं के प्रति राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशील है। प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक विधानसभा से पारित हो गया है। अधिनियम के तहत ऐसे अपराधी जो डरा, धमकाकर, बहला–फुसलाकर बेटियों को बरगलाते हैं, उन्हें आजीवन कारावास की कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रदेश की गुम हुई बेटियों का पता लगाने के लिये ''मुस्कान अभियान'' प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में 9 हजार लापता बेटियों को ढूँढ कर उनके अभिभावकों को सौंपा गया है।

मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने न केवल दुराचार करने वाले अपराधियों को फाँसी की सजा का प्रावधान किया बल्कि अब तक 72 अपराधियों को फाँसी की सजा भी दिलवाई जा चुकी है। बेटियों की आत्म–रक्षा के लिए अपराजिता कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। इसमें पहले चरण में प्रदेश की 23 हजार छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी।

सड़क, पानी, बिजली और सिंचाई में स्व-वित्तपोषित योजनाएं बनाई जाएं : मंत्री गोपाल भार्गव

आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश मंत्री समूह की बैठक सम्पन्न

भोपाल। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि सड़क पानी, बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को आत्म–निर्भर बनाने के लिये स्व–वित्तपोषित योजनाऐं बनाई जाएँ। उन्होंने यह बात आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश अधोसंरचना विकास मंत्री समूह की बैठक में कही। मंत्रालय में आयोजित बैठक में मंत्री समूह में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण (स्वतंत्र प्रभार), नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव सहित संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गण उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश की मूल अवधारणा में सभी जनोपयोगी जन–सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रति निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अधोसंरचना के क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार इस तरह से किया जाए कि योजनाओं के निर्माण से लेकर परिचालन तक की प्रक्रिया स्व–वित्त पोषित कार्यक्रम की तरह संचालित की जा सके। उन्होंने कहा कि बी.ओ.टी. के आधार पर सड़कों का निर्माण महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी क्रम में लोक निर्माण द्वारा राज्य और जिला मार्गों को इसी आधार पर विकसित करने का रोडमेप तैयार किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के 2023 तक सभी ग्रामों को पेयजल की उपलब्ध सुनिश्ति करने क्रम में मध्यप्रदेश में भी तेजी से कार्य किया जा रहा हैं। बैठक में मंत्री समूह द्वारा नल–जल योजनाओं के निर्माण के बाद उनके परिचालन में स्थाई समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्म– निर्भरता प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 21 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता हांसिल की जा चुकी है। लेकिन इनके परिचालन लागत को दृष्टिगत रखते हुए नवकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी कारिडोर परिषण परियोजना पर काम कर रही है।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि मध्यप्रदेश में समस्त स्त्रोतों से एक करोड़ 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जा रहा है। आगामी एक वर्ष में 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार नर्मदाघाटी विकास द्वारा भी सिंचित रकबे में वृद्धि के लिए परियोजनाएँ तैयार की गई है। इनका क्रियान्वयन आगामी तीन वर्ष में किया जाएगा।

आकांक्षा योजना से इस वर्ष जन– जातीय वर्ग के 346 विद्यार्थियों को मिली सफलता

भोपाल। प्रदेश के जन–जातीय विद्यार्थियों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा जैसे आईआईटी, एम्स, नीट, क्लेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये जन–जातीय कार्य विभाग की आर्थिक सहायता से संचालित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। यह संस्थाएँ प्रदेश के 4 संभागीय मुख्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर से संचालित की जा रही हैं। इस वर्ष इन कोचिंग केन्द्रों से आकांक्षा योजना में जेईई मेन्स में 122, जेईई एडवांस में 34, नीट में 86 एवं क्लेट में 104 जन–जातीय विद्यार्थियों को प्रवेश पाने में सफलता मिली है। इस वर्ष इन केन्द्रों में 800 जन–जातीय विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाये जाने का कार्यक्रम विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसके लिये वर्ष 2021–22 के बजट में 10 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने वाले जन–जातीय वर्ग के विद्यार्थियों की फीस देने का कार्य जन–जातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

क्षति का आकलन कर दी जाए सहायता : मुख्यमंत्री श्री चौहान

सरकार किसानों के साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुई बे–मौसम वर्षा के संबंध में आज प्रातः निवास में बैठक में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों में क्षति के आकलन कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाए। बे–मौसम हुई बारिश से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को सर्वे के बाद आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के. के. सिंह, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी उपस्थित थे।

पंचायत में चस्पा हो रिपोर्ट

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सर्वे की रिपोर्ट पंचायत कार्यलय में चस्पा की जाए, जिससे सर्वे में प्राप्त फसलों की क्षति की जानकारी संबंधित किसान को भी प्राप्त हो सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को नियमानुसार फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलवाने का कार्य हो।

जन हानि, पशु हानि पर प्रावधान के अनुसार मदद की जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसलों की हानि के साथ ही जनहानि और पशु हानि के प्रकरणों में भी सहायता दी जाए। जहाँ जन हानि हुई है, प्रावधान अनुसार चार–चार लाख की राशि प्रभावित परिवारों को दी जाए। कृषि विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त निरीक्षण करें। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के प्रावधान के अनुसार पात्र प्रभावितों की पूरी मदद की जाए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में करीब 15 से 20 जिलों में असमय वर्षा हुई है। कहीं–कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। अभी क्षति का आकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त होगा। शुक्रवार की शाम जिलों में बारिश की जानकारी प्राप्त हुई है। पश्चिम मध्यप्रदेश के दो–तीन जिलों में और चंबल क्षेत्र में भी वर्षा हुई है। फसलों की क्षति अधिक नहीं हुई है। यहाँ आंशिक प्रभाव है, उसका आकलन किया जा रहा है। सात लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु की सूचनाएँ मिली हैं। कहीं–कहीं पशु हानि भी रिकार्ड की गई है।

26 लाख से अधिक शिकायतें निराकृत

कॉल–सेंटरों के माध्यम से अप्रैल–2020 से जनवरी–2021 तक प्राप्त सभी 26 लाख 33 हजार 856 शिकायतों को निराकृत कर दिया गया है। उपभोक्ताओं के गलत देयकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये 7 हजार 197 शिविर लगाये गये। इनमें 51 हजार 267 शिकायतों का निराकरण मौके पर ही किया गया।

विद्युत आपूर्ति की नियमित समीक्षा कर कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे और गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनवरी–2021 तक की अवधि में ट्रांसफार्मर फेल होने की दर 8.9 प्रतिशत रही, जबकि गत वर्ष यह 9.6 प्रतिशत दर प्रति 3 माह में मीटर–रीडर की अदला–बदली की व्यवस्था की गई है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

ग्रामोदय मिशन से आएगी खुशहाली ....

कोरोना प्रभावित जिलों में जन–स्वास्थ्य को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धार में स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर बस स्टेण्ड तथा पीथमपुर में शासकीय महाविद्यालय का नया भवन बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं विशेषकर प्रधानमंत्री आवास तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अव्वल 5 राज्यों में शामिल है।

श्री तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 3 लाख से अधिक आवास बन चुके हैं। तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि आज का कार्यक्रम अभूतपूर्व है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्व में पौने दो लाख परिवारों को आवास दिए जा चुके हैं और आज सवा लाख परिवारों को आवास देकर गृह प्रवेश करवाया गया है। यह मध्यप्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में पाँच लाख और हितग्राहियों के लिए आवास बनाए जाएँगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं है।

औद्योगिक निवेश तथा प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगाँव ने आभार माना। कार्यक्रम में सांसद श्री छतर सिंह दरबार, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा, पूर्व मंत्री श्रीमती रंजना बघेल, विधायक श्रीमती नीना–विक्रम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती–मोहन पटेल और पूर्व सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर भी मौजूद थे।

गृह प्रवेश के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के सवा लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात देकर गृह प्रवेश करवाया गया। इन सवा लाख आवासों की लागत 1562 करोड़ रूपये है। ग्रामीण विकास विभाग के साढ़े 10 हजार से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इनमें 6 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर, दो हजार खेल मैदान, दो हजार शांति धाम और 634 पंचायत भवन शामिल हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को 2 हजार करोड़ राशि की विमुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गयी।इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धार जिले के लिए 675 करोड़ रूपए लागत के 94 निर्माण कार्यो का लोकार्पण तथा भूमि–पूजन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भीड़ में सुन ली आदिवासी महिला की पुकार

धार में मिशन ग्रामोदय के कार्यक्रम में ''मुझे मामा से मिलना है'' कहने वाली महिला को ढूँढ कर मिले मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आम जनता के लिए सदैव संवेदनशील रहते हैं। इसका उदाहरण आज धार में आयोजित मिशन ग्रामोदय के राज्य–स्तरीय कार्यक्रम में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा कर ही रहे थे, की भीड़ से एक महिला की आवाज सुनाई पड़ी– ''मुझे मामा से मिलना है।'' मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला की आवाज सुन ली। उन्होंने यह कहते हुए कि ''कोई बहन मुझसे मिलना चाहती है। मैं उसके पास जाना चाहूँगा'' सुरक्षा घेरे से बाहर निकल कर भीड़ में आवाज दी कि– ''कोई बहन मुझसे मिलना चाहती है, वह कहाँ है।'' अधिक जन–समुदाय होने के कारण वे महिला से नहीं मिल सके। मुख्यमंत्री चौहान के मन में तो उसकी आवाज गूँज रही थी। उन्होंने कलेक्टर श्री आलोक सिंह से कहा कि– ''मैं उस बहन से जरूर मिलना चाहूँगा।'' बहुत प्रयास के बाद महिला मिली और वह भी ग्राम लुन्हेरा से आयी ममता निनामा। उसे तत्काल मुख्यमंत्री के पास लाया गया। मुख्यमंत्री ने उस महिला से पूछा कि– ''बहन क्या समस्या है।'' थोड़ी देर तो ममता को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने बताया कि ''ग्राम की सहकारी समिति में सेल्समेन की भर्ती में मैंने भी आवेदन किया था, लेकिन चयन किसी दूसरी पंचायत वाले का हो गया है'' मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ममता निनामा को ढाँढस बँधाया और कलेक्टर को तत्काल प्रकरण की जाँच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

ममता ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि षजिसका मामा इतना दयालु और संवेदनशील हो उसे क्या चिंता, इतनी भीड़ में भी हमारे मामा ने मेरी आवाज सुनी और व्याकुल होकर मुझसे मिले। मैं भगवान को धन्यवाद दूँगी कि ऐसे जन–हितैषी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है।

एक वर्ष में रोग नियंत्रण और अर्थव्यवस्था संभालने में मिली सफलता : मुख्यमंत्री

संचार माध्यमों का सहयोग सराहनीय

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए जहाँ मध्यप्रदेश सरकार पूरी ताकत से कार्य कर रही है, वहीं विभिन्न जन–संचार माध्यम भी जन–जागरूकता बढ़ाने के लिए रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों ने आम जनता को कोरोना से बचने के लिए निरंतर शिक्षित और जागरूक किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बीते एक वर्ष में रोग नियंत्रण और अर्थ–व्यवस्था पटरी पर लाने में सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान रविवार को एक राष्ट्रीय टीवी न्यूज़ चैनल के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश में माफिया के विरुद्ध संचालित अभियान और हरियाली बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।

कोरोना गया नहीं है, हम सभी सावधान रहें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में पड़ोसी राज्य में बढ़े कोरोना के प्रकरणों का दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा बड़े कार्यक्रमों, भीड़ भरे समारोहों और जनता की तरफ से मास्क के उपयोग के प्रति अपेक्षाकृत जागरूकता की कमी से पुनरू कोरोना वायरस फैल रहा है। इसे रोकना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे आम जनता से यह अपील करना चाहते हैं कि गत एक वर्ष में अथक प्रयासों से कोरोना पर नियंत्रण का कार्य हुआ। स्थिति नियंत्रित होते हुए देख कर लोगों में लापरवाही भी दिखने लगी है। उत्सव और मेले होने लगे हैं। इस समय कोरोना वायरस खतरनाक मूड में दिखाई दे रहा है। मध्यप्रदेश में करीब 1300 प्रकरण सामने आए हैं, जो चिंतनीय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे कल भोपाल की सड़कों पर निकले और बाजारों में लोगों को मास्क वितरित किए। हर व्यक्ति को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना है। यदि कोरोना से बचाव का ये उपाय अपनाया जाता है तो हम अवश्य जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चिंतता का भाव आ गया था, उससे प्रकरण बढ़े हैं। अब चूंकि वैक्सीन भी आ गई है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन अवश्य लगवाना है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए जाना चाहिए। फेस मास्क के निरंतर उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से

स्वयं को और परिवार को सुरक्षित भी रखना है।

वायरस पर नियंत्रण और अर्थ–व्यवस्था संभालने पर ध्यान दिया गया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में गत वर्ष मार्च माह में उनके मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के समय काफी कठिन परिस्थितियाँ थीं। राजस्व प्राप्ति नहीं थी। उस समय कोरोना फैलना प्रारंभ हुआ था। अर्थ–व्यवस्था भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। प्रयास सफल हुए और गत वर्ष की तुलना में राजस्व वृद्धि में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में अर्थ–व्यवस्था को संभालने के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में जहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया, वहीं पीएम स्वनिधि योजना से शहरी क्षेत्र के साढ़े तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र के डेढ़ लाख, इस तरह पाँच लाख छोटे कारोबारियों को मदद की गई। मनरेगा में जरूरतमंद लोगों को कार्य देने का रिकार्ड बनाया गया। हुनरमंद लोगों को भी रोजगार दिया गया। लोकल को वोकल बनाने के प्रयास बढ़ाए गए। जहाँ बड़े उद्योग राज्य में आए, वहीं एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। शासकीय नौकरियों में भर्ती से प्रतिबंध हटाया गया।

माफिया के विरुद्ध अभियान में मिली सफलता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि माफिया के विरुद्ध अभियान चलाया गया। विभिन्न तरह के माफिया सक्रिय थे। गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, जमीन पर कब्जा करने वाले, महिलाओं को बहला–फुसलाकर आपराधिक कृत्य करने वाले, अवैध उत्खनन करने वाले, शराब माफिया, चिटफंड कम्पनी के माध्यम से लोगों का पैसा हड़पने वाले अपराधियों के विरुद्ध सरकार ने सख्त कर्रावाई की है। सिर्फ इंदौर में सरकार ने करीब 5 हजार करोड़ रुपये मूल्य के भूखंड सहकारी समितियों से और भू–माफियाओं से वापस दिलवाए हैं। अपराधियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन्हें कारावास में भेजा गया है। वे भागते फिर रहे हैं। यह अभियान जारी रहेगा, हम जनता को राहत देंगे।

जल संरक्षण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य में पुनरू जलाभिषेक अभियान संचालित होगा। नदियों को जोड़ने की पहल की गई थी। नर्मदा और क्षिप्रा को जोड़ा जा चुका है। अन्य नदियों को भी जोड़ा जाएगा। अनेक जल संरचनाएं निर्मित की गई हैं। हर घर में नल से पानी पहुँचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीस लाख आबादी तक नल से जल पहुंचाने का कार्य कर लिया गया है। आने वाले तीन वर्ष में इसका लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

हरियाली का विकास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं वृक्षारोपण प्रतिदिन कर रहा हूँ। कहीं भी जाऊँ, एक पौधा लगाता हूँ। इसे दिनचर्या का अंग बना लिया है। लेकिन यह सिर्फ सरकारी ड्यूटी नहीं है। हर व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर पेड़ लगाना चाहिए।

आने वाली पीढ़ियों को हम रहने योग्य वातावरण उपलब्ध करवाएँ। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक तापमान दो डिग्री बढ़ेगा। ये घातक संकेत है। इसलिए पेड़ लगाना और बचाना जरूरी है। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के प्रयासों से 2 हजार वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। यदि एक परिवार एक पेड़ की सुरक्षा करे तो देश में सवा सौ करोड़ पेड़ लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में गो–काष्ठ का उपयोग बढ़ाएंगे।

गांवों और खेतों में पहुंचकर किसान से मिले : मंत्री सिलावट

भोपाल। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों का भ्रमण किया। विगत दिनों हुई वर्षा, ओलावृष्टि और आँधी से गेहूँ और चना फसल को हुए नुकसान को देखा। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया हुए कहा कि फसलों का पूरा सर्वे कराया जायेगा, जितना भी नुकसान हुआ है, उसकी राहत दिलवाई जायेगी

मंत्री श्री सिलावट ने अपना भ्रमण ग्राम पिवड़ाय से शुरू किया। उन्होंने यहाँ के किसानों से मुलाक़ात की। किसानों ने बताया कि हाल की ओलावृष्टि से गेहूँ की फ़सल को नुक़सान हुआ है। मंत्री श्री सिलावट ने ग्राम कम्पेल, उण्डेल, सेमलिया रायमल का भ्रमण भी किया। सेमलिया रायमल गाँव में किसानों की कटी हुई लहसुन की फ़सल को हुई क्षति को भी देखा। मंत्री श्री सिलावट इसके पश्चात ग्राम सिवनी और डबल चौकी, नागपुर गाँव पहुँचे। एसडीएम ने बताया कि खुड़ेल तहसील के अन्तर्गत ग्राम पिवड़ाय, कम्पेल, पेडमी, तेल्याखेड़ी, भिंगारिया, सेमल्या रायमल, उण्डेल, खराडिया तथा खण्डेल में फसलों की नुकसानी प्रथम दृष्टया आंकलित की गई है।

किसानों से मिलने बाइक पर बैठकर खेतों तक पहुँचे

जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों को देखने के लिए मोटर साइकिल की भी सवारी की। मंत्री श्री सिलावट ग्राम पिवड़ाय में अपना क़ाफ़िला छोड़कर मोटर साइकिल पर बैठे। उन्होंने सकरी गलियों से होते हुए किसानों से मुलाकात की और उसकी समस्याओं को सुना।

धान मिलर्स को प्रोत्साहन राशि 100 रुपये करने पर विचार

भोपाल। खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में उपार्जित धान की मिलिंग/निस्तारण के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार के लिये बनाई गई मंत्री–मण्डलीय उप–समिति की बैठक आज मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा तथा आयुष (स्वतंत्र प्रभार) एवं राज्य मंत्री जल–संसाधन श्री रामकिशोर कॉंवरे उपस्थित थे।

पैक्स को बहुसेवा केन्द्र के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रबंधकों एवं सहायक प्रबंधकों का प्रशिक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में माह मार्च 2021 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधकों के लिए आत्मनिर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजनांतर्गत पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। दिनांक 15 से लेकर 20 मार्च 2021 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण के कुल 02 सत्र आयोजित किए गए। प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुसेवा केन्द्र के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर करना था।

आत्मनिर्भर भारत एवं आत्म मध्यप्रदेश योजनान्तर्गत पैक्स को आत्म निर्भर एवं बहुसेवा केन्द्र बनाने हेतु शासन एवं नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्रता रखने वाली विभिन्न पैक्स को प्याज एवं लहसुन वेयर हाउस निर्माण, ग्रेडिंग/सार्टिंग यूनिट लगाने, कृषि सूचना एवं किसान सुविधा केन्द्र बनाने हेतु चयनित किया जाकर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। डी पी आर में उल्लेखित सभी बिन्दुओं पर जानकारी एवं मार्गदर्शन तथा शंका समाधान हेतु प्रशिक्षण का आयोजन राज्य सहकारी संघ भोपाल द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में डी.पी.आर पर विस्तृत चर्चा एवं विश्लेषण अंतर्गत – बिजनेस प्लान , लक्ष्यपूर्ति, आय सृजन, पुनर्भुगतान आदि पर जानकारी नाबार्ड के सहायक प्रबंधक श्री विवेक गुप्ता द्वारा दी गई। आयुक्त सहकारिता द्वारा जारी परियोजना नियमावली एवं मार्गदर्शिका संचालन पर चर्चा श्री प्रेम द्विवेदी ,उपायुक्त द्वारा की गई। ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट हेतु मशीनों का चयन एवं संचालन पर व्याख्यान श्री आदिनाथ काटे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। वेयर हाउस का निर्माण एवं उसमें ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य, भण्डारण की वैज्ञानिक विधियॉ पर जानकारी श्री एच.एम. त्रिपाठी, से.नि. भण्डारण निरीक्षण अधिकारी एवं क्वालिटी पैरामीटर ट्रेडमार्क, एगमार्क, आई.एस.ओ. सार्टिफिकेशन, एपीडा के गुणवत्ता मापदंड, पैकेजिंग, फारवर्ड लिंकेज पर जानकारी डा. पुरूषोत्तम शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्वालिटी कंट्रोल लबोरेटरी द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त कृषि सूचना एवं किसान सुविधा केन्द्र का संचालन एवं प्रबंधन, उत्पाद में मूल्य संवर्धन एवं विक्रय, नेतृत्व विकास, संप्रेषण कला प्रबंधकीय कौशल, कर्मचारियों की व्यवस्था, पैक्स मैनेजर की भूमिका आदि विषयों पर श्री अभय गोखले, ए जी एम अपेक्स बैंक भोपाल, श्री कपिल पागनीस, कार्यकारी निदेशक आदित्य विजन फॉर डेवलपमेंट श्रीमती रश्मि गोलिया कार्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा रोल प्ले, प्रस्तुतिकरण , समूह चर्चा, व्याख्यान के माध्यम से प्रकाश डाला गया।

दिनांक 15.03.2021 से प्रारंभ प्रशिक्षण के चतुर्थ सत्र में शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, आगर–मालवा, बुरहानपुर, रतलाम एवं डिण्डौरी जिलों के कुल 35 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। दिनांक 17.03.2021 से प्रारंभ पॉचवे सत्र में रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर–मालवा, नीमच एवं मंदसौर जिलों के कुल 24 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन संघ के ओ.एस.डी. श्री संजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समन्वय श्री गणेश प्रसाद मांझी प्राचार्य, श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षिका, श्री संतोष येड़े राज्य समन्वयक एवं श्री विनोद कुशवाहा, सहायक द्वारा किया गया।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना के प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन

इन्दौर। म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, किला मैदान, इन्दौर द्वारा म. प्र. शासन की आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना अंर्तगत कृषि व सहकारिता की भूमिका पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्रो का आयोजन माह मार्च 2021 में किया गया। प्रथम सत्र रतलाम जिले के कार्यालय उपायुक्त सहकारिता में दिनांक 17 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। जिसमें उपायुक्त सहकारिता श्री एस.के. सिंह तथा सहकारिता अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। द्वितीय सत्र रतलाम जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुख्यालय में दिनांक 17 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। जिसमें बैंक महाप्रबंधक श्री आलोक जैन तथा बैंक अधिकारियो व कर्मचारियों ने भाग लिया। तृतीय सत्र मंदसौर जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मुख्यालय में दिनांक 18 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। जिसमें बैंक प्रभारी व उपायुक्त सहकारिता श्री भारत सिंह चौहान तथा बैंक व सहकारिता विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया।

जबलपुर–जिला सहकारी संघ एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सहकारिता विभाग के कार्यपालिक अधिकारियों के लिए सहकारी कार्यशाला का आयोजन संयुक्त आयुक्त सहकारिता पी. के. सिद्धार्थ के निर्देशन में किया गया। राइट टाउन में आयोजित कार्यशाला में सहकारिता विभाग के अंकेक्षण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक, अंकेक्षक तथा उप अंकेक्षक उपस्थित रहे। इस दौरान बी. के. बर्वे तथा एस. चतुर्वेदी ने सहकारी विधान की प्रमुख धाराओं पर व्याख्यान दिया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।